

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

†श्री रंगा (तेनालि) : मैं विनियोग लेखे (रेलवे) १९५५-५६ और १९५६-५७ तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे) १९५७ और १९५८ के बारे में लोक लेखा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

तिब्बत की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, तिब्बत में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में मैं कई वक्तव्य इस सभा में दे चुका हूँ । अन्तिम वक्तव्य मैंने ३ अप्रैल को दिया था, जिसमें मैंने सभा को बताया था कि दलाई लामा अपने बहुत से साथियों के साथ भारतीय राज्य क्षेत्र में आ गये हैं । मैं सभा को अब तक की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ ।

अभी कुछ दिनों पूर्व दलाई लामा अपने दल के साथ मसूरी पहुंच गये हैं जहां सरकार ने उनके ठहरने का इन्तजाम किया है । उसके बाद मैं मसूरी ही आया हूँ और मैंने दलाई लामा से काफी बात-चीत भी की है ।

पिछले कुछ दिनों में हमें समाचार मिला है कि अभी हाल में हजारों तिब्बती लोग हमारे उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण (नार्थ ईस्ट फ्रण्टियर एजेन्सी) के कामिंग सीमान्त डिवीजन में आ गये हैं और कई सौ तिब्बती लोग भूटान राज्य क्षेत्र में भी आ गये हैं । उन्होंने शरण मांगी थी और हमने दे दी है । उनमें से जिन लोगों के पास हथियार थे उनके हथियार ले लिये गये हैं । उनके रहने के लिये एक शिविर में तब तक के लिये व्यवस्था कर दी गयी है जब तक उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार या ऐसे मामलों सम्बन्धी अन्य जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए इधर उधर नहीं भेजा जा सकता । हम इन शरणार्थियों को उनके संसाधनों पर नहीं छोड़ सकते थे । इस मामले में मानवता के अतिरिक्त शान्ति और व्यवस्था का भी सवाल है । इस विषय में आसाम सरकार ने जो सहयोग दिया है, हम उसके लिये आभारी हैं ।

जहां तक दलाई लामा और उनके दल का सम्बन्ध है, हमें उनकी सुरक्षा के लिये तथा भारतीय व विदेशी समाचार-पत्र सम्वाददाताओं की भीड़ से, जो विश्व महत्व के इस मामले में स्वयं उनसे मिल कर जानकारी प्राप्त करने के लिये उत्सुक थे और जो सम्भवतः उनको तथा उनके दल को परेशान कर देते, उनको बचाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ी । हम दलाई लामा तथा उनके दल की सुरक्षा के लिये उत्सुक तो थे ही, लेकिन साथ ही यह भी चाहते थे कि समाचार-पत्रों के लोगों को उनसे मिलने का समुचित अवसर भी दिया जाये । हमें तेजपुर से लगभग ७५ पत्र प्रतिनिधियों तथा समाचार अभिकरणों से इस आशय के आवेदन पत्र मिले थे कि उन्हें दलाई लामा से बात करने का अवसर दिया जाये । अतः वैदेशिक कार्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को पहले से ही तेजपुर भेज दिया गया ताकि वह वहां पत्र प्रतिनिधियों तथा फोटोग्राफरों से, जो वहां इकट्ठे थे, मिल कर ठीक प्रबन्ध करे । इस पदाधिकारी ने दलाई लामा से मिलने तथा उनका फोटो लेने सम्बन्धी पत्र प्रतिनिधियों की मांग को यथासम्भव पूर्ण करने के लिये समुचित प्रबन्ध किया । भारत में प्रवेश करने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के शीघ्र बाद ही दलाई लामा ने एक वक्तव्य देने की इच्छा प्रकट की। बाद में हमें सूचित किया गया कि यह वक्तव्य तेजपुर में दिया जायेगा। हमारे पदाधिकारी ने वक्तव्य के अनुवाद को पत्र सम्वाद-दाताओं में बटवाने का प्रबन्ध कर दिया।

चूंकि कुछ गैर-जिम्मेदारीपूर्ण आरोप लगाये गये हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि वह बात स्पष्ट कर दूँ कि उस वक्तव्य के लिये तथा उसके बाद मसूरी में दिये गये एक छोटे वक्तव्य के लिये स्वयं दलाई लामा ही पूर्णतः उत्तरदायी थे। इन वक्तव्यों का मसविदा तैयार करने या उन्हें तैयार करने में हमारे पदाधिकारियों का कोई हाथ नहीं था।

सभा को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि दलाई लामा अपनी इच्छा से ही भारत में आये। हमने कभी भी यह सुझाव नहीं दिया था कि वह भारत में आ जायें। हाँ, हमें इस बात की सम्भावना थी कि शायद वह भारत में शरण मांगें और जब उन्होंने शरण मांगी, तो हमने उन्हें शरण देना स्वीकार कर लिया। चूंकि वह भारत के एक दूरस्थ कोने से होकर भारत में घुसे, अतः हमारे सामने परिवहन, संगठन तथा सुरक्षा की विशेष समस्या पैदा हो गयी थी। हमने दलाई लामा और उनके दल से बोम डीला में मिलने और उन्हें मसूरी तक पहुंचाने के लिये एक पदाधिकारी नियुक्त कर दिया। इस पदाधिकारी को इस काम के लिये इसलिये चुना गया कि वह पहले लासा में हमारे वाणिज्य दूत के रूप में रह चुका था अतः वह दलाई लामा तथा उनके पदाधिकारियों से थोड़ा बहुत परिचित था। दलाई लामा के ठहरने के लिये मसूरी को उनकी मर्जी का पता लगाने के बाद ही चुना गया। ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि हम उन पर कोई अनुचित प्रतिबन्ध लगायें, पर विशेष स्थिति होने के कारण कुछ प्रबन्ध करना आवश्यक ही था ताकि कोई गड़बड़ न हो जाये। ध्यान रहे कि तिब्बत में होने वाली अनेक घटनाओं के प्रति जिनके परिणामस्वरूप दलाई लामा को लासा छोड़ कर भारत आना पड़ा, भारत की जनता तथा संसार के समाचार-पत्रों में बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गयी थी। मसूरी पहुंचने के बाद जनता तथा पत्र-प्रतिनिधियों की भीड़ से, दलाई लामा को परेशान किये जाने से बचाने के लिए कुछ उपाय किये गये। इसके अतिरिक्त दलाई लामा के कहीं आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गयी। उनसे कह दिया गया है कि वह और उनके दल के लोग अपनी इच्छानुसार मसूरी में घूम सकते हैं।

तथ्य ये है पर इनके पीछे कुछ गंभीर बातें हैं, जिनके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तिब्बत में दुखपूर्ण घटनायें हुई हैं और हो रही हैं। लोग निर्बाध उद्वेगों से काम ले रहे हैं। तरह-तरह के आरोप लगाये गये हैं और ऐसी बातें कही गयी हैं जिनसे स्थिति और भी खराब हो सकती है और हमारे उत्तरी पड़ोसी के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा मेरी बात से सहमत होगी कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में हमें संयम व बुद्धिमानी से काम करना चाहिए तथा उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस शीत युद्ध के समय में, ऐसा देखा गया है कि लोग बिना संयम के कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं और प्रायः बिना किसी औचित्य के गंभीर आरोप भी लगाते हैं। सौभाग्य से हम इस शीत युद्ध से अलग रहे हैं और हमें आशा है कि इस मामले में भी, जैसा कि हम पहले करते आये हैं, हम शीत युद्ध की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यह मामला बहुत गंभीर है और इस संबंध में उत्तेजित होकर कुछ कहना या करना ठीक नहीं है। अतः जनता और समाचार-पत्रों से मेरी अपील है कि वे संयम के साथ भाषा का प्रयोग करें। मुझे खेद है कि कभी-कभी हमारी ओर से कुछ गलतियाँ हुई हैं। खास तौर से मुझे इसका खेद है कि अभी कुछ दिनों पूर्व चीन राज्य के प्रधान, श्री माओ से तुंग के चित्र

का अपमान किया गया था। यह घटना बम्बई में हुई थी और कुछ बेजिम्मेदार लोगों ने ऐसा किया था। किसी घटना से उत्तेजित होकर हमें ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए।

चीन के नेताओं, अखबारों तथा जनता से ऐसी कोई अपील करने का मुझे हक नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि चीन के कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों ने कुछ अनुचित बातें कही हैं और भारत के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। उन्होंने सत्यता और औचित्य का ध्यान किये बिना शीत युद्ध की भाषा का प्रयोग किया है। खेद की बात है कि हजारों वर्षों की सभ्यता वाला तथा अपने संयमपूर्ण व विनम्र व्यवहार के लिए प्रसिद्ध महान देश ऐसा कोई आचरण करे। भारत के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, वे इतने ऊलजलूल हैं कि मैं उनके बारे में कुछ भी कह नहीं पा रहा हूँ। एक आरोप यह है कि हमने दलाई लामा को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती यहां रख रखा है। चीनी पदाधिकारियों को यह मालूम होगा कि हमारे देश की क्या कार्य प्रणाली है तथा हमारे देश में क्या विधियां हैं और क्या हमारा संविधान है। यदि हम चाहते भी, तो भी हम दलाई लामा को उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार के निरोध में नहीं रख सकते थे, लेकिन इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ऐसा करना चाहते हैं। इससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हमारे सामने कठिन समस्याएँ पैदा हो जायें। फिर भी, इस मामले को आसानी से सुलझाया जा सकता है। दलाई लामा को खुली छूट है कि वह कभी भी तिब्बत या जहां भी कहीं वह चाहें, जा सकते हैं। चूंकि पंचन लामा ने कुछ बड़े अजीब वक्तव्य दिये हैं, अतः मैंने यह कहा है कि वह भारत आकर स्वयं दलाई लामा से मिल सकते हैं। यदि वह आयें तो भारत उनका स्वागत करेगा। मैंने यह भी कहा है कि चीनी राजदूत या चीन सरकार का अन्य कोई दूत इस संबंध में भारत आ सकता है और दलाई लामा से मिल सकता है। शान्तिपूर्वक भारत में आने पर किसी पर कोई रोक नहीं है और हम चाहे उनकी बात से सहमत हों या न हों, पर हम उनका स्वागत अतिथि के रूप में करेंगे।

एक और अजीब आरोप “भारतीय विस्तारवादियों” के बारे में लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये लोग ब्रिटेन की साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी परम्परा का अनुकरण कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि ब्रिटेन की नीति तिब्बत के संबंध में विस्तारवादी थी और उन्होंने इस शताब्दी के शुरू में बल का प्रयोग करके सीमा में अपना विस्तार किया था। हमारे मतानुसार ब्रिटेन की यह कार्यवाही अनुचित व निर्दयतापूर्ण कार्यवाही थी जिसने तिब्बत की जनता को बहुत हानि पहुंचाई। उसी के परिणामस्वरूप उस समय की भारत की ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत में कुछ राज्य क्षेत्रातीत अधिकार प्राप्त कर लिये थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनमें कुछ अधिकार भारत को विरासत में मिले। चूंकि हम किसी भी देश में ऐसे अधिकार रखने के विरुद्ध थे, अतः हम इन अधिकारों को भी अपने पास नहीं रखना चाहते थे। स्वतंत्रता व भारत विभाजन के बाद, सभा को पता है, हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां थी। अतः हम तिब्बत की ओर ध्यान नहीं दे सके। चूंकि हमें ऐसा कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिससे हम लासा में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते, अतः कुछ समय तक हमने ब्रिटिश प्रतिनिधि को ही लासा में रहने दिया। उसके बाद हमने एक भारतीय को उस पद पर नियुक्त किया। जब चीनी सेनायें तिब्बत में घुसीं, उसके तुरन्त बाद ही राज्य-क्षेत्रातीत अधिकारों का सवाल पैदा हुआ और हम तुरन्त उन अधिकारों को छोड़ने को राजी हो गये। तिब्बत में चाहे कुछ भी होता, हम तो इन अधिकारों को छोड़ ही देते। हमने तिब्बत के कुछ स्थानों से अपनी सेना की टुकड़ियों को वापस बुला लिया और भारतीय डाक व तार घरों तथा विश्राम गृहों को हमने वहां के लोगों को दे दिया। हमने तिब्बत के सामने पंचशील के सिद्धान्त

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

रखे तथा एक नये आधार पर तिब्बत से संबंध स्थापित किये। हम सिर्फ यह चाहते थे कि तीर्थ यात्रा संबंधी यातायात और व्यापार के संबंध में तिब्बत के साथ हमारे पुराने संबंध कायम रहें। उसके बाद हमने जो कुछ भी किया वह इस बात का सबूत है कि तिब्बत के मामले में हमारी यही नीति रही और तिब्बत में हमारा कोई राजनैतिक या अन्य स्वार्थ नहीं था। वास्तव में यदि हम संकीर्ण दृष्टिकोण से भी देखें, तो भी पता लगेगा कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी नीति को अपनाना गलत व व्यर्थ होता। तब से अब तक हमने केवल इस समझौते का ही पालन करने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि चीन राज्य तथा वहां की जनता के साथ मित्रता बढ़ाने का भी भरसक प्रयत्न किया है।

अतः यह हमारे लिए बड़े खेद तथा आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातें हमारे बारे में कही गयीं, जो कि अशोभनीय तथा बिल्कुल सारहीन हैं। हमने चीन सरकार को इस खेद के संबंध में सूचित कर दिया है, विशेष तौर से पीकिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के चालू अधिवेशन में दिये गये भाषणों के संबंध में।

कुछ समय पूर्व मैंने बताया था कि हमारी नीति के तीन मुख्य आधार हैं : (१) भारत की सुरक्षा तथा अखंडता का रक्षण; (२) चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाये रखने की इच्छा और (३) तिब्बत की जनता के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति। हम इसी नीति का पालन करेंगे क्योंकि केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी हम इसे एक सही नीति समझते हैं। यदि एशिया के दो बड़े देश, भारत और चीन के बीच, जो युगों से शान्तिपूर्ण पड़ोसी की तरह रहते आये हैं, शत्रुता की भावना पैदा हो जायेगी तो यह एक बड़ी दुखपूर्ण घटना होगी। हम तो इस नीति का पालन करेंगे ही पर हमें आशा है कि चीन भी ऐसा ही करेगा और ऐसी कोई बात या कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे हमारे दोनों देशों के मित्रतापूर्ण संबंधों को खतरा पैदा हो। हमारे दोनों देशों की मित्रता एशिया और विश्व की शान्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पंचशील के सिद्धान्तों में परस्पर सम्मान करने की बात भी है। यदि झूठे आरोप लगाये जायेंगे और शीत युद्ध की सी भाषा का इस्तेमाल किया जायेगा, तो परस्पर सम्मान का गं होगा।

मैं पहले यह बता चुका हूँ कि यह आरोप बिल्कुल अनुचित है कि कालिम्पोंग तिब्बत के विद्रोह का केन्द्र था। तिब्बती उद्भव के बहुत से लोग भारत में भारतीय राष्ट्रजनों के रूप में रहते हैं। ये लोग दलाई लामा का बहुत सम्मान करते हैं। तिब्बत में हुई घटनाओं से इनमें से कुछ को बहुत क्षोभ हुआ है और निस्सन्देह कुछ के विचार चीन विरोधी हैं। हमने उनको साफ शब्दों में बता दिया है कि भारत में रहकर उन्हें किसी प्रकार की विध्वंसकारी कार्यवाही नहीं करने दी जायेगी और मैं यह कहूंगा कि सामान्य रूप से उन्होंने भारत सरकार के इस आदेश का पालन भी किया है। यदि चुपके-चुपके किसी ने कुछ किया हो, तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। पर यह कहना या सोचना, कि कालिम्पोंग में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने मिलकर तिब्बत के विद्रोह का संचालन किया, मैं समझता हूँ ख्यालों की उड़ान भरना और सचाई से आंख फेरना है।

खम्पा विद्रोह आज से तीन साल से पहले तिब्बत की सीमा के पास चीन के मुख्य प्रदेश में शुरू हुआ था। क्या उसके लिए कालिम्पोंग जिम्मेदार है? धीरे-धीरे यह विद्रोह फैलता गया,

और अधिकांश तिब्बत निवासियों के दिमाग पर, जो इस विद्रोह में सम्मिलित नहीं थे, इसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उनमें अपने भविष्य के बारे में भय तथा संदेह उत्पन्न हो गया था और राष्ट्रीयता की भावना उनमें जाग उठी। हो सकता है कि उनका भय अकारण ही रहा हो, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें भय था। ऐसी भावनाओं को सम्य उपायों से ही शान्त किया जा सकता है न कि झगड़े या युद्ध द्वारा।

दो-तीन वर्ष पूर्व जब प्रधान मंत्री चाऊ-एन लाई भारत आये थे, तो उन्होंने तिब्बत के बारे में मुझ से स्पष्ट व काफी विस्तृत बातों की थीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि यद्यपि काफी समय से तिब्बत चीन राज्य का एक भाग रहा है, पर उन्होंने तिब्बत को कभी भी चीन के एक प्रान्त के रूप में नहीं समझा है। तिब्बत के लोग मुख्य चीन के लोगों में भिन्न हैं जैसे कि चीन राज्य के अन्य स्वायत्त-शाली प्रदेशों के लोग चीन के लोगों से भिन्न हैं, यद्यपि वे प्रदेश चीन राज्य के ही भाग हैं। अतः वे तिब्बत को स्वायत्तशासी प्रदेश समझते थे। उन्होंने आग यह भी बताया कि यह सोचना एक दम गलत है कि चीन तिब्बत पर साम्यवाद जबरदस्ती लादेगा। किसी पिछड़े देश पर इस प्रकार साम्यवाद नहीं लादा जा सकता और ऐसा करने का उनका इरादा भी नहीं था, यद्यपि वे चाहते हैं कि वहां धीरे-धीरे सुधार हों। लेकिन वह यह भी चाहते थे कि इन सुधारों को अभी काफी समय तक के लिए स्थगित रखा जाये। लगभग उसी समय दलाई लामा भी यहां आये हुये थे। उनसे भी मैंने अच्छी तरह बातों की थीं। मैंने उन्हें बताया कि प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई का रवैया तिब्बत के प्रति मित्रतापूर्ण है और मैंने उन्हें चाऊ-एन-लाई के उस आश्वासन की भी बात बताई कि वह तिब्बत की स्वायत्तता का सम्मान करेंगे। मैंने दलाई लामा को सुझाव दिया कि वह इन आश्वासनों को स्वीकार कर लें और वहां स्वायत्तता बनाये रखने तथा कुछ सुधार लागू करने के मामले में सहयोग दें। दलाई लामा ने यह स्वीकार किया कि यद्यपि उनका देश आध्यात्मिक दृष्टि से काफी उन्नत है, पर सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है और वहां सुधारों की आवश्यकता है।

हम नहीं कह सकते कि इन मित्रतापूर्ण इरादों तथा विचारों को कहां तक कार्यान्वित किया गया। लेकिन परिस्थितियां कठिनाईपूर्ण थीं। एक ओर तो एक प्रगतिशील समाज था और दूसरी ओर एक ऐसा समाज था जो परिवर्तन को पसंद नहीं करता था और जिसे भय था कि परिवर्तन के बहाने न जाने क्या किया जाय। दोनों समाजों में काफी अन्तर था और उनमें कोई बीच का रास्ता निकलने की आशा नहीं थी। इस बीच तिब्बत में कुछ रूप में परिवर्तन आया। संचार साधनों का तीव्रता से विकास किया गया और तिब्बत की पृथकता को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया। यद्यपि भौतिक सीमाओं को दूर कर दिया गया पर बौद्धिक व भावनात्मक सीमायें बढ़ गईं। ऐसा लगता है कि इन बौद्धिक व भावनात्मक सीमाओं को दूर करने का या तो प्रयत्न नहीं किया गया था उसमें सफलता नहीं मिली।

यह कहना कि तिब्बत के “उच्चवर्ग के कुछ प्रतिक्रियावादियों” ने यह विद्रोह किया, इस जटिल स्थिति को असाधारण रूप से सरल बनाने का प्रयास प्रतीत होता है। चीनी साधनों तक से जो विवरण प्राप्त हुआ है, उससे भी पता लगता है कि तिब्बत का विद्रोह काफी बड़े पैमाने पर था और इसका आधार राष्ट्रीयता की तीव्र भावनायें रही होंगी, जो केवल उच्चवर्ग के लोगों को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी प्रभावित करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि इसके साथ ही स्वार्थी लोग भी इसमें शामिल हो गये और उन्होंने इससे लाभ उठाने की कोशिश की।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जब इन दुखद घटनाओं की खबर भारत में आई, तो यहां उसकी तुरन्त भारी प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया में सरकार का कोई हाथ नहीं था और न यह केवल राजनैतिक प्रतिक्रिया ही थी। वह प्रतिक्रिया भावना तथा मानवीय आधारों पर मुख्यतः सहानुभूति की प्रतिक्रिया थी। साथ ही तिब्बत की जनता के साथ भारत की जनता का जो पुराना धार्मिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है, उसके कारण भी भारत की जनता में प्रतिक्रिया हुई। यह भी सच है कि भारत में कुछ लोगों ने इस प्रतिक्रिया की धारा को एक अन्य दिशा में ले जाकर इससे लाभ उठाने की कोशिश की। यह पर यह सच है कि भारतीय जनता में इसकी प्रतिक्रिया हुई। जब भारत में इतनी प्रतिक्रिया हुई, तो आप समझ सकते हैं कि तिब्बत के लोगों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। संभवतः एशिया के अन्य बौद्ध धर्मावलम्बी देशों में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है। जब इस प्रकार की प्रबल भावनाएँ हैं, जो कि सिर्फ राजनैतिक ही नहीं हैं, तो केवल राज-नैतिक उपायों से उनको शान्त नहीं किया जा सकता, सैनिक उपायों से तो उन्हें शान्त किया ही नहीं जा सकता। तिब्बत के मामले में दखल देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि चीन व भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बने रहें, पर साथ ही तिब्बत की जनता के साथ हमें पूर्ण सहानुभूति है और उनकी दयनीय अवस्था पर हमें बहुत क्षोभ है। हमें आशा है कि चीन के अधिकारी तिब्बतवासियों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि तिब्बत प्रदेश की स्वायत्तता के संबंध में उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसके अनुसार वे मित्रतापूर्ण सहयोग से तिब्बत की जनता को जीतने का प्रयत्न करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कि हमें आशा है कि इस समय जो मार धाड़ चल रही है वह बन्द हो जायेगी।

मैं बता चुका हूँ कि ३ दिन पूर्व मैं मसूरी में दलाई लामा से मिला था और मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि वहां उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहां की स्थिति से लोगों में कितना रोष है, कैसे उन्होंने उन्हें संयम में रखने की कोशिश की। उन्होंने यह भी बताया कि उनका ख्याल था कि बौद्धधर्म, जो उन्हें अपने जीवन से भी अधिक प्यारा है, खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्तिम क्षण तक भी वह लासा छोड़ने को इच्छुक नहीं थे। १७ मार्च की दोपहर के बाद, जब उनके महल की ओर कुछ गोलियां चलाई गयीं और कुछ गोलियां निकट के एक तालाब में गिरी, तो अचानक ही उन्होंने लासा छोड़ने का निश्चय किया। कुछ ही घंटों में उन्होंने और उनके दल ने लासा छोड़ दिया और भारत की सीमा की ओर प्रस्थान किया। लासा को छोड़ने का काम इतनी जल्दी में किया गया कि पर्याप्त कपड़े आदि भी साथ में नहीं लिए जा सके। जब मैं दलाई लामा से मिला, तो उनके दल का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। दुभाषिया भी हमारा ही अपना था। दलाई लामा ने बताया कि जो दोनों वक्तव्य उनके नाम से निकाले गये हैं वे उनके ही थे और किसी ने भी दबाव डाल कर उनसे ऐसा नहीं करवाया है। यद्यपि अभी उनकी आयु थोड़ी ही है, पर मैं नहीं समझता कि उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उनसे कोई काम कराया जा सकता है। मुझे उनके प्रति पूर्ण सहानुभूति है; इतनी छोटी आयु में उन्हें भारी बोझ उठाना पड़ रहा है तथा इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में उन पर काफी शारीरिक व बौद्धिक जोर पड़ा है। मैंने उन्हें राय दी है कि वे कुछ समय तक आराम करें और जल्दी में कोई निश्चय न करें। तिब्बत की दशा के संबंध में उन्हें बहुत खेद था और वह चाहते थे कि वह लड़ाई बिल्कुल बन्द हो जाये।